न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के सामने,

मेसर्स महेंद्र एंड महिंद्रा एल. टी. वी.-याचिकाकर्ता
बनाम
कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल और एक और-उत्तरदाता

2010 की सीडब्ल्यूपी संख्या 17157
24 जुलाई, 2012

(ए) भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-रिट अधिकार क्षेत्र-अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970-कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण-सुनवाई की प्रक्रिया-याचिकाकर्ता-कंपनी और पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड का 2009 में विलय-पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड के 22 कर्मचारी और ठेकेदार सहित 5 अन्य मार्च 1991 में आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। - एक ही मामले में तीन अलग-अलग तिथियां देने वाले तीन अलग-अलग आदेश-चूक में मामले को खारिज करने का आदेश केवल आरंभ किया गया था और उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का कोई हस्ताक्षर या पदनाम नहीं था-जिस तरीके में कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही की सराहना नहीं की गई थी-न्यायाधिकरण द्वारा कोई उचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया था-2 साल से अधिक समय तक सुनवाई की तारीख के बिना मामला बांधना-प्रत्यर्थी द्वारा अदालत को दिया गया स्पष्टीकरण-न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत जवाब में आयुक्त-न्यायाधिकरण के विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया कि जिस तरीके से अधिकरण द्वारा कार्यवाही की गई है, उसकी सराहना नहीं की जा सकती है। सबसे पहले जैसा कि पहले ही ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, अपील में सुनवाई की तारीखों का कोई ट्रैक नहीं था जब यह 28/4/2006 को दायर किया गया था। इसे 24/7/2006 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था, जिस तारीख को इसे 23/10/2006 तक स्थगित कर दिया गया था। 23/10/2006 के लिए दो ऑर्डर रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। दोनों आदेशों में सुनवाई की अगली तारीख अलग-अलग तय की गई थी। एक में यह 24/1/2007 था जबकि दूसरे में यह 7/2/2007 है। फिर भी 7/12/2006 और 21/2/2007 को अभिलेख पर दो अन्य आदेश उपलब्ध हैं जो उपर्युक्त दो आदेशों में से किसी में भी नियत सुनवाई की तारीखें नहीं थीं। मामले को निर्धारित दो तिथियों में से किसी पर भी नहीं लिया गया था जो 24/1/2007 या 7/2/2007 थीं, बल्कि इसे दिनांक 7/12/2006 के आदेश में निर्धारित तिथि पर लिया गया था जो 30/5/2007 था। इस तारीख की सुनवाई का नोटिस एपीएफसी चंडीगढ़ को 23/2/2007 को 30/5/2007 के लिए भेजा गया था। मामले को 31/7/2007 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके पश्चात्, अभिलेख पर अगला आदेश दिनांक 21/9/2007 को दिया गया है जिसमें मामले को 14/12/2007 तक स्थगित कर दिया गया है।

para 17

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि दिनांक 21/9/2007 के पूर्वोक्त आदेश द्वारा सुनवाई की तारीख 14/12/2007 नियत किए जाने के पश्चात् फाइल पर ऐसा कोई आदेश नहीं है जिससे यह दर्शाता हो कि अपील में सुनवाई की तारीख 19/5/2010 को चंडीगढ़ में नियत की जाए। किस प्राधिकार के अधीन पक्षकारों को 19/5/2010 की तारीख के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था, यह अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। इसके अभाव में कोई नोटिस भी जारी नहीं किया जा सकता था। इससे पहले भी दो साल से अधिक की अवधि के लिए मामला बिना किसी सुनवाई की तारीख के पड़ा हुआ था। इसका कारण जैसा कि अदालत में समझाया गया था कि कोई पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था।

para 18

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभी भी यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि उपरोक्त नोटिस दिनांक 3/4/2010 कभी भी याचिकाकर्ता को दिया गया था। जिस तरीके से उपरोक्त सूचना भेजी गई थी, वह भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह दावा किया जाता है कि अपील को 19/5/2010 को चंडीगढ़ में सुनवाई के लिए लिया गया था, लेकिन उस तारीख के लिए कोई आदेश रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। यदि उस तारीख को कुछ कार्यवाही हुई थी तो आदेश पत्र तैयार किया जाना चाहिए था। 31/5/2010 को पारित आदेश, जिसमें अपील खारिज कर दी गई थी, कहीं भी यह नहीं दर्शाता है कि इसकी सुनवाई 19/5/2010 को चंडीगढ़ में हुई थी और आदेश सुरक्षित रखा गया था। सुनवाई की तारीख के अलावा किसी भी आदेश की तारीख संभवतः उस मामले में हो सकती है जहां वकीलों या पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखे गए हों। यद्यपि प्रत्यर्थी आयुक्त द्वारा अपने उत्तर में लिया गया स्टैंड यह है कि 19/5/2010 को मामला 31/5/2010 के आदेश के लिए आरक्षित था, लेकिन वही ट्रिब्यूनल के समक्ष रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत है, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है।

para 19

(ख) भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 226-कार्यवाहियों के संचालन के तरीके के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि न्यायाधिकरण को जारी किए गए निर्देश-महत्वपूर्ण अर्ध न्यायिक कार्य का निर्वहन करने वाले न्यायाधिकरण-वकील या पक्षों की उपस्थिति में पारित किए जाने वाले आदेश-पक्षकारों को नोटिस की सेवा के तरीके प्रस्तावित।

अभिनिर्धारित किया कि आदेश से विदा होने से पहले यह न्यायालय कार्यवाही के संचालन के तरीके पर टिप्पणी करना चाहेगा। जैसा कि ऊपर पहले ही देखा जा चुका है कि मामले को तारीख के हिसाब से नहीं लिया जा रहा था, जिसका अर्थ है सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर। सुनवाई की दो अलग-अलग तारीखें तय करते हुए एक तारीख को दो अलग-अलग आदेश पारित किए गए हैं। न्यायाधिकरण महत्वपूर्ण अर्ध-न्यायिक कार्य कर रहा है। मामलों को उस तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है जिस तरह से वर्तमान मामले में निपटाया गया है। कुछ ज़िम्मी आदेशों में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उस आदेश पर किसने हस्ताक्षर किए थे। न तो उस व्यक्ति का नाम और न ही उसके पदनाम का उल्लेख किया गया है जिसने उस पर हस्ताक्षर किए थे। भविष्य में यह निर्देश दिया

जाता है कि सभी अंतरिम या अंतिम आदेशों में जो भी अधिकरण द्वारा अपील या अन्य कार्यवाहियों में पारित किए जाते हैं, उन आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

para 25

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां लिखित रूप में होती हैं। जैसा कि टाइल वर्तमान मामले में 21/9/2007 के पश्चात् दर्शाती है जब मामला 14/12/2007 तक स्थगित कर दिया गया था केवल एक सूचना अभिलेख पर उपलब्ध है जो चंडीगढ़ में 19/5/2010 के रूप में सुनवाई की तारीख नियत करती है। किसी भी तारीख को फाइल लेने और सुनवाई की अगली तारीख तय करने और पक्षों को नोटिस जारी करने का कोई आदेश नहीं है। इसकी अनुपस्थिति में किस प्राधिकरण के तहत पक्षों को नोटिस जारी किया गया था, यह रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। न्यायाधिकरण का प्रमुख स्थान दिल्ली में है। जैसा कि सूचित किया गया था कि कभी-कभी यह विभिन्न स्थानों पर सर्किट बेंच रखता है। सर्किट बेंच में जो भी मामले तय किए जाने हैं, एक विशेष बेंच में मामले को तय करने वाली फाइल में विशिष्ट आदेश होना चाहिए। उपर्युक्त आदेश या तो वकीलों या पक्षों की उपस्थिति में पारित किया जाना चाहिए जब यह प्रधान पीठ में सूचीबद्ध हो या यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नोटिस वास्तव में दोनों पक्षों को दिया गया है। सुनवाई के लिए जो भी अपील की जाती है, उस तारीख को कार्यवाही को दर्शाते हुए रिकॉर्ड पर एक अंतरिम आदेश पारित किया जाना चाहिए। पक्षकारों को नोटिस की सेवा सुनिश्चित करने का एक तरीका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से हो सकता है क्योंकि प्रतिष्ठान आम तौर पर उस क्षेत्र से संबंधित होता है। हम तकनीक के युग में जी रहे हैं। संचार के साधनों के लिए भी इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी प्रतिष्ठानों के पास फैक्स या ईमेल के माध्यम से नोटिस की एक प्रति भेजने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि यह सफल होता है तो इसे भविष्य में नोटिस की सेवा के तरीके के रूप में अपनाया जा सकता है। इसके अलावा अपील दायर करने वाले वकील को भी सूचित किया जाना चाहिए। एक ही ईमेल के माध्यम से भी हो सकता है. At अपील दायर करने के समय यह एक आवश्यकता होनी चाहिए कि पार्टी और वकील जिन्होंने अपील दायर की है, उन्हें अपना पूरा पता टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर और ईमेल पता प्रदान करना चाहिए ताकि ट्रिब्यूनल को उनके साथ संवाद करने में सक्षम बनाया जा सके।

para 26.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पी. के. मुतनेजा

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए संजय तंगरी अधिवक्ता।

आवेदक की ओर से रीता कोहली अधिवक्ता।

निर्णय

जस्टिस राजेश बिंदल

1. याचिकाकर्ता ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (संक्षेप में, 'ईपीएफ अधिनियम') की धारा 7-ए के तहत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त चंडीगढ़ (संक्षेप में, 'आयुक्त') द्वारा पारित दिनांक 8/11/1996 (अनुलग्नक पी-20) आदेश दिनांक 31/5/2010 (अनुलग्नक पी-22) को कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली (संक्षेप में, 'ट्रिब्यूनल') द्वारा उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए पारित किया है; आदेश दिनांक 18/8/2010 (अनुलग्नक पी-24) याचिकाकर्ता द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर आवेदन को खारिज करते हुए दिनांक 31/5/2010 के एकतरफा आदेश को रद्द करने के लिए; और मांग नोटिस दिनांक 15/9/2010 (अनुलग्नक पी-25) वसूली अधिकारी द्वारा जारी किया गया।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक ऐसी कंपनी है जिसमें पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड (संक्षेप में, 'पीटीएल') नामक एक अन्य कंपनी का 16/2/2009 को विलय किया गया था। पी. टी. एल. को शुरू से ही ई. पी. एफ. अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया था। यह ईपीएफ अधिनियम के तहत नियमित रूप से योगदान कर रहा था। प्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मचारियों के अलावा, प्रतिष्ठान ने कुछ ठेकेदारों को भी नियुक्त किया था जो अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (संक्षेप में, 1970 अधिनियम) के तहत विधिवत पंजीकृत थे। ठेकेदार अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के रिकॉर्ड का प्रबंधन कर रहे थे और स्वतंत्र रूप से ईपीएफ अधिनियम के प्रावधानों का पालन कर रहे थे। मार्च 1991 में, एक दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी में पीटीएल के 22 कर्मचारियों और 5 अन्य व्यक्तियों को आतंकवादियों ने एक कर्मचारी बस का अपहरण करने के बाद गोली मार दी थी। उस घटना में तत्कालीन ठेकेदार की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में, ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों के संबंध में अंशदान के भुगतान में स्पष्ट रूप से देरी हुई थी।

3. भविष्य निधि आयुक्त ने याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्त ठेकेदारों, ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों की संख्या और 1980 के बाद से उन्हें किए गए भुगतान का विवरण मांगा। नोटिस 18/4/1995 को जारी किया गया था। विवरण प्रस्तुत करने और प्रस्तुत करने में असमर्थता दिखाने के बावजूद, कुछ अभिलेख बहुत पुराने होने के कारण, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियों पर विचार किए बिना, आयुक्त ने दिनांक 8/11/1996 के आदेश द्वारा 1980 से मार्च 1995 की अवधि के लिए 131 कर्मचारियों के संबंध में 22,27,919/- के बकाया का आकलन किया। उपरोक्त मांग को 1996 की सिविल रिट याचिका संख्या 19472 दायर करके इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी। उपर्युक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 1/7/1997 से प्रभावी आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण का गठन किया गया था। इस अदालत ने रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्ता को अपील दायर करके आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ किया था। याचिका दायर की गई थी। एक अंतरिम उपाय के रूप में, ट्रिब्यूनल ने बैंक गारंटी देने के अधीन विवादित आदेश पर रोक लगा दी। अपील दिल्ली में ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित रही। चूंकि 2007 के बाद से कोई पीठासीन अधिकारी नहीं था, इसलिए इसे सुनवाई के लिए नहीं लिया गया और सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की गई थी। अचानक इसे 19/5/2010 को चंडीगढ़ में सर्किट बेंच में सुनवाई के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके लिए

याचिकाकर्ता को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था। केवल दिनांक 31/5/2010 का आदेश प्राप्त हुआ था जिसमें याचिकाकर्ता के वकील की अनुपस्थिति में योग्यता पर अपील को खारिज कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद फाइल का निरीक्षण किया गया और एकतरफा आदेश को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर किया गया। उसी को 18/8/2010 के आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का निवेदन है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की निंदा की गई है। न्यायाधिकरण, जो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण निष्क्रिय था, ने अचानक चंडीगढ़ में अपील की सुनवाई निर्धारित कर दी थी, जिसके लिए याचिकाकर्ता को कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कोई भी सुनवाई के समय याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप अपील को एकतरफा खारिज कर दिया गया। ट्रिब्यूनल ने अपील के साथ आगे बढ़ने से पहले यह नहीं पूछा कि नोटिस की सेवा याचिकाकर्ता पर प्रभावित हुई थी या नहीं। जब एकतरफा आदेश को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर करके यह बताया गया था, तो प्रार्थना पर विचार करने की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी न्यायाधिकरण ऐसा करने में विफल रहा और आवेदन को खारिज कर दिया। प्रार्थना दोनों आदेशों को दरकिनार करने और याचिकाकर्ता को अपील में सुनवाई का अवसर देने के लिए है।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील नं। 2 ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपील दायर किए जाने के बाद इसे चंडीगढ़ में सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था। न्यायाधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित नोटिस दिया गया था। इसकी सेवा की गई होगी। वास्तव में, याचिकाकर्ता को मामले पर नज़र रखनी चाहिए थी। याचिकाकर्ता की सुविधा के लिए मामला चंडीगढ़ में तय किया गया था क्योंकि प्रतिष्ठान इसी क्षेत्र से संबंधित है। यह कहने के लिए एक विचार के बाद है कि याचिकाकर्ता को नोटिस नहीं मिला था, बल्कि यह एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता अपील पर सुनवाई के दौरान उपस्थित होने में विफल रहा। संभवतः हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है।

6. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना और पेपर बुक के साथ-साथ ट्रिब्यूनल के रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिसे तलब किया गया था।

7. वर्तमान रिट याचिका के निर्णय के प्रयोजन के लिए इस न्यायालय को विवाद के गुण-दोष में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह केवल अपील का निर्णय करते समय अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है जिस पर जाने की आवश्यकता है। ईपीएफ अधिनियम की धारा 7-ए के तहत आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 8/11/1996 के आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने शुरू में 1996 की सिविल रिट याचिका संख्या 19472 दायर की थी, जिसे 17/2/2006 को निम्नलिखित आदेश पारित करके निपटाया गया थाः

पक्षकारों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत हैं कि याचिकाकर्ता को पहले कर्मचारी भविष्य निधि और गलत अधिनियम, 1952 की धारा 7 (डी) के 2010 (4) की सिविल रिट याचिका संख्या 17157 के तहत दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि

अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क करना चाहिए। तदनुसार उपरोक्त शर्तों में एक निर्देश जारी किया जाता है।

इस बीच 19/12/1996 को दिया गया अंतरिम आदेश आज से तीन महीने की अवधि के लिए लागू होगा। याचिकाकर्ता को अपील दायर करने के लिए तीन महीने का समय भी दिया जाता है। प्रत्यर्थी अपील के मनोरंजन के समय सीमा के संबंध में कोई याचिका नहीं लेने का भी वचन देते हैं।

8. इसके संदर्भ में, याचिकाकर्ता ने कोई समय गंवाए बिना 28/4/2006 को अधिकरण के समक्ष अपील दायर की, जिसे 24/7/2006 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था, जिस तिथि को इसे 23/10/2006 तक स्थगित कर दिया गया था। 23/10/2006 को, फ़ाइल पर दो आदेश हैं। आदेश में से एक में कहा गया है कि अपीलार्थी के वकील को गुणदोष के आधार पर सुना गया था और प्रतिवादी के वकील के बीमार होने के कारण मामले को 24/1/2007 तक स्थगित कर दिया गया था। जबकि एक अन्य आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा दायर अंतरिम रोक के लिए आवेदन को अपील के निपटारे तक इसके पुनर्वैधीकरण के अधीन पहले से प्रस्तुत बैंक गारंटी के अधीन अनुमति दी गई थी। 7/2/2007 के लिए प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था। 23/10/2006 को पारित किए गए उपरोक्त दो आदेश नीचे दिए गए हैं।–

"23-10-2006

"उपस्थित
श्री जे. के. चौधरी, अपीलार्थी के वकील।
श्री राजीव रंजन राजेश, प्रत्यर्थी के प्रॉक्सी वकील।
"अपीलार्थी के विद्वान वकील को गुणदोष के आधार पर सुना गया है। चूंकि प्रतिवादी का विद्वान वकील बीमार है, इसलिए मामले को 24/1/2007 को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया है।

23-10-2006

उपस्थितः

अपीलार्थी की ओर से श्री पी. डी. माहेश्वरी, अधिवक्ता।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7-ए के तहत निर्धारित राशि के बराबर एक बैंक गारंटी प्रत्यर्थी के पक्ष में प्रस्तुत की गई है। उक्त बैंक गारंटी फरवरी, 2007 तक वैध है। उन्होंने 75% पूर्व-जमा की छूट के लिए एक आवेदन और अधिनियम की धारा 7-0 भी दायर की है। आवेदन की अनुमति प्रत्यर्थी के साथ तैयार बैंक गारंटी के अधीन है। प्रत्यर्थी के विवादित आदेशों पर बैंक गारंटी की वैधता तक रोक लगा दी गई है। आसानी से बैंक गारंटी को अपील के निपटारे तक फिर से मान्य किया जाता है, तब तक रोक जारी रहेगी।

7-2-2007 के लिए प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया जाए।

9. उपरोक्त दोनों आदेशों में सुनवाई की अलग-अलग अगली तारीख तय की गई थी। एक क्रम में यह 7/2/2007 था, जबकि दूसरे क्रम में 24/1/2007 था। ट्रिब्यूनल द्वारा जिस तरह से कार्यवाही की गई, उस पर ध्यान देना काफी अजीब है। 7/12/2006 को एक अन्य आदेश पारित किया गया है, जो कि दो पूर्वोक्त आदेशों के संदर्भ में नियत तारीख नहीं थी जब 30/5/2007 के लिए प्रत्यर्थी को ताजा नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था। वही नीचे निकाला गया हैः-

"प्रतिवादी को रजिस्ट्रार के समक्ष 30-5-2007 तक वापस करने योग्य नया नोटिस जारी किया जाए। सेवा और अभिवचन पूरा करने के बाद मामले को आगे के आदेशों के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष रखा जा सकता है।"

10. फाइल पर 21/2/2007 को हस्ताक्षरित एक और टिप्पण है, जो उपरोक्त निर्दिष्ट तीन आदेशों में से किसी में भी सुनवाई की तारीख नहीं थी, जिसमें अपील को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। इसका पाठ नीचे निकाला गया है

अपील डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दी जाती है।

अभिलेखों में फाइल भेजें।

आदेश की प्रति दोनों पक्षों को जारी करें।

Sd/- 21.2.2007.

11. यह स्पष्ट नहीं है कि उपरोक्त आदेश पर किसने हस्ताक्षर किए थे। न तो संबंधित व्यक्ति के नाम और न ही पदनाम का उल्लेख किया गया है क्योंकि यह केवल शुरू किया गया है। फाइल पर एक अन्य दस्तावेज सहायक भविष्य निधि आयुक्त चंडीगढ़ को दिनांक 23/2/2007 को जारी किया गया नोटिस है, जिसमें सुनवाई की अगली तारीख 30/5/2007 बताई गई है। यह स्पष्ट रूप से फाइल पर दिनांक 7/12/2006 के आदेश के संदर्भ में है जिसे पहले ही ऊपर संदर्भित किया जा चुका है। 30/5/2007 को, मामले को 3/7/2007 तक स्थगित कर दिया गया। इस आदेश से भी यह स्पष्ट नहीं है कि उस पर किसने हस्ताक्षर किए थे।

12. अभिलेख के पृष्ठ 96 पर एक सूचना उपलब्ध है जो 30/11/2006 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, चंडीगढ़ को 7/2/2007 के लिए जारी की

गई थी।

13. 31/7/2007 को पारित कोई आदेश फाइल पर उपलब्ध नहीं है। अगला आदेश दिनांक 21/9/2007 है जिसमें याचिकाकर्ता के वकील की उपस्थिति को चिह्नित करते हुए, यह नोट किया गया है कि अपीलार्थी ने बैंक गारंटी की एक प्रति दाखिल की है और मामले को जवाब दाखिल करने के लिए 14/12/2007 तक स्थगित कर दिया गया था। यह आदेश स्पष्ट रूप से उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है जिसने 21/2/2007 को आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन फिर भी यह उसकी पहचान या पदनाम का खुलासा किए बिना है। इसके बाद; सुनवाई की किसी भी तारीख के लिए मामले को स्थगित करने या 19/5/2010 को शिविर कार्यालय चंडीगढ़ में तारीख तय करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई आदेश उपलब्ध नहीं है। तथापि पृष्ठ 97 पर अभिलेख पर दिनांक 3/4/2010 की सूचना उपलब्ध है जिससे पता चलता है कि अपील की सुनवाई 19/5/2010 को चंडीगढ़ में नियत की गई है। नोटिस एपीएफसी चंडीगढ़ और अपीलार्थी/पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड के अपीलार्थी/वकील को भेजा गया था।

14. जिस तरीके से उपरोक्त सूचना भेजी गई थी और यह भी कि क्या संबंधित पक्षों को यह सूचना दी गई थी या नहीं, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है। 19/5/2010 को कोई कार्यवाही अभिलेख पर नहीं है जब मामले की सुनवाई शिविर कार्यालय, चंडीगढ़ में की जानी बताई जाती है। अधिकरण द्वारा दिनांक 31/5/2010 के आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि आदेश की प्रति पक्षकारों को भेजी जाए जो दिनांक 1/6/2010 के संप्रेषण द्वारा याचिकाकर्ता को भेजी गई थी। आदेश में सुनवाई की तारीख नहीं बताई गई है।

15. उपर्युक्त आदेश की प्राप्ति के बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 31/5/2010 के एकतरफा आदेश को अलग करने के लिए 7/7/2010 को एक आवेदन दायर किया, जिसमें विशेष रूप से कहा गया था कि चंडीगढ़ में सुनवाई की अगली तारीख 19/5/2010 निर्धारित करने वाला दिनांक 3/4/2010 का नोटिस याचिकाकर्ता पर लागू नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कोई भी सुनवाई के समय याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया था कि रिकॉर्ड पर नोटिस की सेवा का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 19/5/2010 के लिए कोई ऑर्डर शीट नहीं है। प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने के बाद, उपरोक्त आवेदन को भी निम्नलिखित आदेश पारित करके दिनांक 18/8/2010 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया थाः –

"अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31/5/2010 के एक्सपार्ट आदेश को इस

आधार पर खारिज करने के लिए दायर आवेदन पर अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं कि अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

रिकॉर्ड से पता चलता है कि मामला 19/5/2010 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था और पक्षों को उचित नोटिस दिया गया था। हालांकि, अपीलार्थी अपील करने और अपना मामला रखने में विफल रहा और मामला 31/5/2010 के आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया। दिनांक 31/5/2010 का आदेश मामले के गुण-दोष पर पारित किया गया था। चूंकि, अपीलार्थी अपना मामला रखने के लिए उसे प्रदान किए गए अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा, इसलिए इस स्तर पर उसे यह कहने की अनुमति नहीं है कि आदेश एकतरफा है। "

16. उपर्युक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अभिलेख पर कोई सामग्री होने के बिना, न्यायाधिकरण द्वारा यह देखा गया था कि सुनवाई की तारीख 19/5/2010 निर्धारित करने के लिए नोटिस पक्षों को दिया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता सुनवाई के अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा, इसलिए अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया गया।

17. न्यायाधिकरण द्वारा जिस तरह से कार्यवाही की गई है, उसकी सराहना नहीं की जा सकती है। सबसे पहले, जैसा कि पहले ही ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, अपील में सुनवाई की तारीखों का कोई ट्रैक नहीं था जब यह 28/4/2006 को दायर किया गया था। इसे 24/7/2006 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था, जिस तारीख को इसे 23/10/2006 तक स्थगित कर दिया गया था। 23/10/2006 के लिए, रिकॉर्ड पर दो ऑर्डर आर्क उपलब्ध हैं। दोनों आदेशों में सुनवाई की अगली तारीख अलग-अलग तय की गई थी। एक में यह 24/1/2007 था जबकि दूसरे में यह 7/2/2007 है। फिर भी 7/12/2006 और 21/2/2007 को अभिलेख पर दो अन्य आदेश उपलब्ध हैं, जो उपर्युक्त दो आदेशों के संदर्भ में नियत सुनवाई की तारीखें नहीं थीं। मामला 24/1/2007 या 7/2/2007 नियत दो तारीखों में से किसी पर भी नहीं लिया गया था, बल्कि इसे दिनांक 7/12/2006 के आदेश में नियत तिथि पर लिया गया था जो 30/5/2007 था। इस तारीख की सुनवाई का नोटिस एपीएफसी चंडीगढ़ को 23/2/2007 को 30/5/2007 के लिए भेजा गया था। मामले को 31/7/2007 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तत्पश्चात, अभिलेख पर अगला आदेश दिनांक 21/9/2007 को दिया गया है जिसमें 14/12/2007 को स्थगन किया गया है।

18. उपर्युक्त आदेश दिनांक 21/9/2007 द्वारा सुनवाई की तारीख 14/12/2007 नियत किए जाने के पश्चात् फाइल पर ऐसा कोई आदेश नहीं है

जिससे यह दर्शाता हो कि अपील में सुनवाई की तारीख 19/5/2010 को चंडीगढ़ में नियत की जाए। किस प्राधिकारी के अधीन पक्षकारों को 19/5/2010 के रूप में सुनवाई की तारीख के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था, यह अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। इसके अभाव में कोई नोटिस भी जारी नहीं किया जा सकता था। इससे पहले भी दो साल से अधिक की अवधि के लिए मामला बिना किसी सुनवाई की तारीख के पड़ा हुआ था। इसका कारण जैसा कि अदालत में समझाया गया था कि कोई पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था।

19. फिर भी यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि उपरोक्त नोटिस दिनांक 3/4/2010 कभी याचिकाकर्ता को दिया गया था। जिस तरीके से उपरोक्त सूचना भेजी गई थी, वह भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह दावा किया जाता है कि अपील को 19/5/2010 को चंडीगढ़ में सुनवाई के लिए लिया गया था, लेकिन उस तारीख के लिए कोई आदेश रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। यदि उस तारीख को कुछ कार्यवाही हुई थी, तो आदेश पत्र तैयार किया जाना चाहिए था। 31/5/2010 को पारित आदेश, जिसमें अपील खारिज कर दी गई थी, कहीं भी यह नहीं दर्शाता है कि इसकी सुनवाई 19/5/2010 को चंडीगढ़ में हुई थी और आदेश सुरक्षित रखा गया था। सुनवाई की तारीख की तुलना में किसी भी आदेश की तारीख संभवतः उस मामले में हो सकती है जहां वकीलों या पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखे गए हों। यद्यपि प्रत्यर्थी-आयुक्त द्वारा अपने उत्तर में लिया गया रुख यह है कि 19/5/2010 को मामला 31/5/2010 के आदेश के लिए आरक्षित था, लेकिन वही अधिकरण के समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत है, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है।

20. अधिकरण द्वारा दिनांक 18/8/2010 के आदेश में यह तथ्य कि पक्षकारों को नोटिस दिया गया था, बिना किसी आधार के है। इसके समर्थन में रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।

21. उपर्युक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के पास एकमात्र विकल्प यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 31/5/2010 और 18/8/2010 के आदेशों को और एकतरफा आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन को भी रद्द कर दिया जाए।

22. तदनुसार आदेश दिया।

23. पक्षकारों ने अपने वकीलों के माध्यम से अब आगे की सुनवाई के लिए 3/9/2012 को दिल्ली में अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

24. चूंकि मामला गुण-दोष पर विचार करने के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया गया है, मेरी राय में श्रमिक संघ द्वारा दायर आवेदन में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह निपटाया जाता है।

25. आदेश से अलग होने से पहले यह अदालत कार्यवाही के संचालन के तरीके पर टिप्पणी करना चाहेगी। जैसा कि ऊपर पहले ही देखा जा चुका है कि मामले को सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर तारीख-वार नहीं लिया जा रहा था। सुनवाई की दो अलग-अलग तारीखें तय करते हुए एक तारीख को दो अलग-अलग आदेश पारित किए जाते हैं, न्यायाधिकरण महत्वपूर्ण अर्ध-न्यायिक कार्य का निर्वहन कर रहा है। मामलों को उस तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है जिस तरह से वर्तमान मामले में निपटाया गया है। कुछ ज़िम्मी आदेशों में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उस आदेश पर किसने हस्ताक्षर किए थे। न तो उस व्यक्ति का नाम और न

ही उसके पदनाम का उल्लेख किया गया है जिसने उस पर हस्ताक्षर किए थे। भविष्य में यह निर्देश दिया जाता है कि सभी अंतरिम या अंतिम आदेशों में जो भी अधिकरण द्वारा अपील या अन्य कार्यवाहियों में पारित किए जाते हैं, उन आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाएगा।

26. अदालतों में सभी कार्यवाही लिखित रूप में होती हैं। जैसा कि फाइल से पता चलता है कि वर्तमान मामले में 21/9/2007 के पश्चात्, जब मामला 14/12/2007 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, केवल एक सूचना अभिलेख पर उपलब्ध है जिसमें चंडीगढ़ में सुनवाई की तारीख 19/5/2010 नियत की गई है। किसी भी तारीख को फाइल लेने और सुनवाई की अगली तारीख तय करने और पक्षों को नोटिस जारी करने का कोई आदेश नहीं है। इसकी अनुपस्थिति में, किस अधिकार के तहत पक्षों को नोटिस जारी किया गया था, यह अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। न्यायाधिकरण का प्रमुख स्थान दिल्ली में है। जैसा कि सूचित किया गया था, कभी-कभी, यह विभिन्न स्थानों पर सर्किट बेंच रखता है। सर्किट बेंच में जो भी मामले तय किए जाने हैं, एक विशेष बेंच में मामले को तय करने वाली फाइल में विशिष्ट आदेश होना चाहिए। उपर्युक्त आदेश प्रधान पीठ में सूचीबद्ध होने पर वकीलों या पक्षों की उपस्थिति में पारित किया जाना चाहिए या यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नोटिस वास्तव में दोनों पक्षों को दिया गया है। सुनवाई के लिए जो भी अपील की जाती है, उस तारीख को कार्यवाही को दर्शाते हुए रिकॉर्ड पर एक अंतरिम आदेश पारित किया जाना चाहिए। पक्षकारों को नोटिस की सेवा सुनिश्चित करने का एक तरीका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि प्रतिष्ठान आम तौर पर उस क्षेत्र से संबंधित होता है। हम तकनीक के युग में जी रहे हैं। संचार के साधनों के लिए भी इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जहाँ भी प्रतिष्ठानों के पास फैक्स या ईमेल आईडी है, वहाँ उस माध्यम से भी नोटिस की एक प्रति भेजने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि यह सफल होता है, तो इसे भविष्य में नोटिस की सेवा के तरीके के रूप में अपनाया जा सकता है। इसके अलावा, अपील दायर करने वाले वकील को भी सूचित किया जाना चाहिए। ईमेल के माध्यम से भी ऐसा ही हो सकता है। अपील दायर करने के समय, यह एक आवश्यकता होनी चाहिए कि पक्षकार और अपील दायर करने वाले वकील को अपना पूरा पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल पता प्रदान करना चाहिए ताकि न्यायाधिकरण उनके साथ संवाद कर सके।

27. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-सहायक भविष्य निधि आयुक्त के समक्ष कार्यवाही में नोटिस आदि की सेवा के लिए इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

28. आदेश की एक प्रति केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली को भेजी जाए।

29. रिट याचिका का निपटान तदनुसार किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के

लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सूर्य करण चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)